बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 152 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 31 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

मेट्रो ट्रैक पर गिरने से एक व्यक्ति घायल, संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा; अस्पताल में कराया गया भर्ती

नई दिल्ली । विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर सोमवार सुबह मेट्रो ट्रैक पर गिरने से एक व्यक्ति घायल हो गया। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति की पहचान करावल नगर निवासी 52 साल के अनिल कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मेट्रो पुलिस उपायुक्त भरत रेड्डी ने बताया कि सोमवार सुबह विश्वविद्यालय मेट्रो के कंट्रोलर से सूचना मिली कि विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर एक व्यक्ति मेट्रो ट्रैक पर कूद गया है और घायल हो गया है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घायल यात्री को मेट्रो कर्मी पहले ही हिंदू राव अस्पताल पहुंचा चुके थे। घायल अनिल कुमार ने पुलिस को बताया कि वह ट्रैक पर इसलिए गिर गया क्योंकि उसका संतुलन बिगड़ गया था।

जनगणना 2026- पहले चरण के लिए 33 सवाल तय- ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी दे सकेंगे; लिव-इन कपल को शादीशुदा का दर्जा मिलेगा

नई दिल्ली । जनगणना-2026 का पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसमें 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके मुताबिक, स्थिर रिश्ते में रहने वाले लिव-इन कपल्स को भी शादीशुदा माना जाएगा। ऐसा तब ही होगा जब कपल मानेगा कि उनका रिश्ता लंबा चलने वाला है। पहले फेज के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहां लोग खुद अपनी जानकारी भर सकेंगे।

उनकी मदद के लिए इस पोर्टल पर FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल) भी दिए गए हैं। यह चरण 'हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना' कहलाता है। इसका मकसद देश में घरों और बुनियादी सुविधाओं की जानकारी जुटाना है, ताकि सरकार बेहतर योजनाएं बना सके। दूसरे चरण में आबादी से जुड़ी डिटेल जानकारी ली जाएगी।

जनगणना आयुक्त बोले- रेफरेंस डेट बहुत महत्वपूर्ण

भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण कहते हैं, जनगणना की संदर्भ तिथि (रेफरेंस डेट) बहुत महत्वपूर्ण है। संदर्भ समय 1 मार्च की आधी रात है, जो 28 फरवरी 2027 और 1 मार्च 2027 के बीच पड़ती है। इस संदर्भ तिथि का उल्लेख 16 जून 2025 को जारी पहली अधिसूचना में किया गया था, जिसमें जनगणना कराने के इरादे की घोषणा की गई थी। इसी संदर्भ तिथि के कारण इसे जनगणना 2027 कहा जाता है। 16 जून, 2025 को अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 ही बनी हुई है। जनगणना के परिणामों से प्रत्येक प्रशासनिक इकाई, राय, जिले, गांव और वार्ड की जनसंख्या और विभिन्न आंकड़ों की एक झलक मिलेगी, जैसा कि वे 1 मार्च, 2027 को 00:00 बजे की स्थिति में होंगे। इसलिए यह संदर्भ तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जनगणना दो चरणों में की जाती है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना है, जिसमें घरों की सूची बनाना और उनकी गिनती करना शामिल है।

पहला फेज 1 अप्रैल 2026 से

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 8 जनवरी को बताया था कि देश में होने वाली जनगणना 2027 का पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा। हर राय और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां 30 दिनों में यह

काम पूरा करेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने (सेल्फ एन्यूमरेशन) का विकल्प भी दिया जाएगा। दरअसल, जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। यह अब 2027 में पूरी होगी।

जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी

सरकार ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। करीब 30 लाख कर्मचारी मोबाइल एप के जरिए जानकारी जुटाएंगे। मोबाइल एप, पोर्टल और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर से जनगणना बहुत हद तक पेपरलेस होगी। ये ऐप Android और iOS दोनों पर काम करेंगे। जाति से जुड़ा डेटा भी डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा।

आजादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति की गिनती शामिल होगी। इससे पहले अंग्रेजों के समय 1931 तक जाति आधारित जनगणना हुई थी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने अप्रैल में लिया था। 2011 की पिछली जनगणना के अनुसार, भारत की आबादी करीब 121 करोड़ थी, जिसमें लगभग 51.5फीसदी पुरुष और 48.5फीसदी महिलाएं थीं।

मैप पर हर घर 'डिजी डॉट' बनेगा, इसके 5 फायदे होंगे

1. आपदा में सटीक राहत- जियो टैगिंग से बना डिजिटल लेआउट मैप बादल फटने, बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा के समय उपयोगी साबित होगा। सुदूर हिमालयी क्षेत्र में बसे किसी गांव में बादल फटने जैसी घटना के समय इस मैप से तुरंत पता चल जाएगा कि किस घर में कितने लोग रहते हैं। होटलों में क्षमता के हिसाब से कितने लोग रहे होंगे। इस ब्योरे से बचाव के लिए जरूरी तमाम नौका, हेलिकॉप्टर, फूड पैकेट आदि की व्यवस्था करने में मदद मिलेगी।

2. परिसीमन में मदद मिलेगी- राजनीतिक सीमाएं जैसे संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों का युक्तिसंगत तरीके से निर्धारण करने में भी इससे मदद मिलेगी। जियो टैगिंग से तैयार मैप से यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का संतुलित बंटवारा कैसे हो। समुदायों को ऐसे न बांट दिया जाए कि एक मोहल्ला एक क्षेत्र में और दूसरा मोहल्ला किसी अन्य क्षेत्र में शामिल हो जाए। घरों के डिजी डॉट से डिलिमिटेशन (परिसीमन) की प्रक्रिया में आसानी होगी।

3. शहरी प्लानिंग में आसानी- शहरों में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों या पार्कों की प्लानिंग करने में भी यह मैप उपयोगी साबित होगा। अगर किसी जगह के घरों के डिजिटल लेआउट में बच्चों की अधिकता होगी तो पार्क और स्कूल प्राथमिकता से बनाने की योजना तैयार की जा सकेंगी। यदि किसी बस्ती में कच्चे मकानों या खराब घरों की अधिकता दिखेगी तो वहां किसी मेडिकल इमरजेंसी के समय तत्काल मोबाइल राहत वैन भेजी जा सकेंगी।

4. शहरीकरण और पलायन दर का डेटा मिलेगा- इस जनगणना के दस साल बाद होनी वाली जनगणना में डिजिटल मैप के परिवर्तन आसानी से दर्ज किए जा सकेंगे। देश के विभिन्न हिस्सों में शहरीकरण की दर और पलायन के क्षेत्रों की मैपिंग की तुलना सटीक ढंग से की जा सकेगी।

5. मतदाता सूची से डुप्लीकेट नाम हट जाएंगे- आधार की पहचान के साथ जियो टैगिंग मतदाता सूची को सटीक और मजबूत बनाने में सहायक होगी। जब वोटर किसी भौगोलिक स्थान से डिजिटली जुड़ा होगा तो दोहरे पंजीकरण के समय उसके मूल निवास का पता भी सामने आएगा।

नई योजना बेअसर- वीबी-जी राम जी कानून पर खरगे ने सरकार को घेरा, कहा- मनरेगा कमजोर कर मजदूरों को छोड़ा बेसहारा

नई दिल्ली ।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मनरेगा के तहत मिलने वाले काम के अधिकार को खत्म कर दिया और नई घोषित योजना का जमीनी स्तर पर कोई असर नहीं दिख रहा। खरगे ने कहा कि इससे लाखों मजदूरों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। खरगे ने कहा कि सरकार ने जिस वीबी-जी-राम जी योजना का प्रचार किया। वह जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कोविड काल की बात करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि उसी समय मनरेगा ने लाखों मजदूरों को राहत दी थी। अब हालात यह हैं कि कई रायों में काम बंद होने की शिकायतें आ रही हैं।

क्या मनरेगा में काम बंद होने के आरोप हैं?

खरगे ने कहा कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पिछले 87 दिनों से 12,000 मजदूर काम न मिलने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दावा

किया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई रायों से भी मनरेगा के काम रुकने की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ जगहों पर अधिकारियों को नए काम शुरू न करने के निर्देश मिलने की भी बात कही जा रही है।

वीबी-जी राम जी योजना का जमीनी असर कितना?

कांग्रेस का आरोप है कि 21 दिसंबर 2025 को अधिसूचित की गई वीबी-जी राम जी योजना का कोई असर नहीं दिख रहा है। खरगे ने कहा कि सरकार ने इसका खूब प्रचार किया, लेकिन मजदूरों को इसका कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुरानी योजना कमजोर की जा रही है, तो नई योजना लागू क्यों नहीं हो रही।

क्या सीएजी रिपोर्ट में भी सामने आई कमियां?

खरगे ने महाराष्ट्र की सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले पांच साल में मनरेगा के तहत स्वीकृत कामों में से 53 प्रतिशत से भी कम पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 2.5 लाख काम ऐसे हैं, जो शुरू ही नहीं हो पाए। इससे यह साफ होता है कि योजना को कमजोर किया गया है।

क्या मजदूरों की हालत और खराब हुई है?

खरगे ने कहा कि एलपीजी की कमी और उद्योगों की खराब स्थिति के कारण कई मजदूर शहरों से गांव लौटने को मजबूर हुए हैं। लेकिन गांव में भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे मजदूरों की आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है।

सरकार पर क्या है मुख्य आरोप?

कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने मनरेगा को कमजोर कर दिया है और मजदूरों के अधिकार छीन लिए हैं।

खरगे ने कहा कि कोविड जैसे मुश्किल समय में मनरेगा ने लोगों को सहारा दिया था, लेकिन अब सरकार उस व्यवस्था को खत्म कर रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि मनरेगा और रोजगार का मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। ग्रामीण इलाकों में काम और आय की कमी का असर चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है।

राजधानी में बदला मौसम का मिजाज, कई हिस्सों में बारिश; गर्मी से मिली राहत

नई दिल्ली ।

राजधानी दिल्ली और एनसीआर से सटे शहरों में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवा के बाद बारिश हुई। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था। अचानक हुए इस परिवर्तन के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं धूल भरी आंधी और फिर बारिश के कारण कुछ इलाकों में जाम की स्थित बन गई। मौसम विभाग के पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी कि 30 मार्च को आसमान में बादल छाए रहेंगे और दोपहर से शाम के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं, 31 मार्च को भी आसमान में बादल बने रहेंगे और दिन में बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि तापमान अधिकतम 29-31 डिग्री और न्यूनतम 19-21 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 1 अप्रैल को आसमान में बादल बने रहेंगे और तापमान 31-33 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। 2 अप्रैल को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तापमान अधिकतम 32-34 डिग्री तक रहेगा। इसके अलावा, 3 अप्रैल को फिर से बादल छाए रहेंगे और दिन में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30-32 डिग्री और न्यूनतम 18-20 डिग्री के बीच रहेगा। मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार, मार्च में यह असामान्य मौसम उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहे पश्चिमी विक्षोभों की एक श्रृंखला से जुड़ा है। साथ ही, 15 मार्च से सक्रिय ये विक्षोभ इस बार सामान्य से कम ऊंचाई पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनका प्रभाव भी गहरा हो गया है। यही वजह है कि दिल्ली के मौसम का मिजाज भी इन दिनों बदला-बदला सा है। अधिकारियों के अनुसार, इसके प्रभाव से दिल्ली के कुछ हिस्सों में दिन में तेज हवाएं चलने, हल्की बारिश होने और हल्की धूल भरी आंधी की संभावना है, हालांकि, मौजूदा मौसम गतिविधियों का तापमान पर कोई खास असर पड़ने के आसार नहीं है।

दिल्ली नगर निगम कानून में बड़े बदलाव की तैयारी, छोटे उल्लंघन अपराध की श्रेणी से होंगे बाहर

नई दिल्ली ।दिल्ली में शहरी प्रशासन को अधिक नागरिक-अनुकूल और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में प्रस्तावित संशोधनों के जरिए छोटे नागरिक अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और नियमों को सरल बनाने की पहल की गई है. इन बदलावों का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई के बजाय सहयोग और अनुपालन आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिससे नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास मजबूत हो सके. प्रस्तावित संशोधनों के तहत कई ऐसे प्रावधानों में बदलाव किया जा रहा है, जिनमें पहले छोटे-छोटे उल्लंघनों पर आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान था. अब ऐसे तकनीकी या मामूली मामलों में मुकदमा चलाने के बजाय उन्हें तर्कसंगत तरीके से निपटाने की योजना है. इससे अनावश्यक कानूनी दबाव, सामाजिक कलंक और लंबी मुकदमेबाजी से राहत मिलेगी.

छोटे मामलों में जेल की सजा खत्म करने की तैयारी

नगर निगम से जुड़े मामूली उल्लंघनों, खासकर रोजगार और लाइसेंसिंग से जुड़े मामलों में कारावास के प्रावधान को पूरी तरह समाप्त करने का प्रस्ताव है. यह बदलाव इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि छोटे नागरिक मामलों को आपराधिक अपराध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए.

पुराने और अप्रासंगिक नियमों को हटाने की पहल

कई ऐसे प्रावधान, जिनमें बहुत कम जुर्माना निर्धारित था और जो वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो चुके हैं, उन्हें हटाने का प्रस्ताव रखा गया है. इन प्रावधानों को अब प्रशासनिक उपायों के जरिए बेहतर ढंग से संभालने की दिशा में काम किया जाएगा.

व्यापार और जीवन को आसान बनाने पर फोकस

लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाकर बाजार, व्यापार और खान-पान से जुड़े व्यवसायों को राहत देने की कोशिश की गई है. आपराधिक सजा के बजाय आर्थिक दंड लागू करने से व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी, अनुपालन का बोझ घटेगा और अधिक व्यवसाय औपचारिक ढांचे में आएंगे.

संतुलित दंड से बढ़ेगी जिम्मेदारी

कुछ मामलों में बार-बार या गंभीर उल्लंघनों को रोकने के लिए दंड को बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है. हालांकि इसमें संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके.

'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए सड़कों पर उतरे युवा, बैरिकेडिंग ने छात्रों को संसद तक पहुंचने से रोका

नई दिल्ली। संसद का बजट सत्र पहले से ही गरमाया हुआ है और वहीं आज (30 मार्च) संसद की सड़कों पर एक बार फिर युवा आवाजें गूंज उठीं है. 'वन नेशन वन इलेक्शन' को जल्द से जल्द लागू करने की मांग को लेकर संविधान सुरक्षा सपोर्ट ग्रुप ने देशभर से छात्रों को दिल्ली बुलाया था. दिल्ली के ली मेरिडियन होटल से शुरू हुए आज के इस प्रोटेस्ट मार्च में हजारों युवा शामिल हुए, जो आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, जामिया मिल्लिया जैसे संस्थानों से आए हैं.

संसद में जो लोग चुने हैं, वे हमारी बात सुनें- जनरल सेक्रेटरी

युवाओं की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने भी पहले से ही पूरी तैयारी की हुई थी. दिल्ली पुलिस ने पूरा इलाका छावनी में बदल दिआ था और संसद भवन पहुंचने से काफी पहले ही दो लेयर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, वहीं आरएएफ की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गईं थी, ताकि कोई भी छात्र संसद परिसर की ओर न बढ़ पाए. संविधान सुरक्षा सपोर्ट के जनरल सेक्रेटरी नवीन ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि संसद में जो

लोग चुने हुए हैं, वे हमारी बात तो सुन लें. हम देश के युवा हैं और यहां की आबादी का लगभग 50 फीसदी हम जैसे युवा ही हैं. अगर हमारी बात अनसुनी रह गई तो फिर आखिर किसकी सुनी जाएगी? हमारी मांग साफ है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से जल्द लागू हो. बार-बार चुनावों की वजह से जो आर्थिक संकट पैदा होता है, वन नेशन आने इलेक्शन से उस होने वाले आर्थिक संकट पर लगाम लग जाएगी.

300 से यादा सांसद, हमें लिखित समर्थन दे रहे हैं

जेपीसी रिपोर्ट में हो रही देरी पर नवीन ने कहा कि, हमें इस देरी से कोई मतलब नहीं हम जेपीसी कमेटी से मिल चुके हैं. हमने लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की है और 300 से यादा सांसदों से भी बात हो चुकी है और ये सब सांसद हमें लिखित समर्थन दे रहे हैं तो उन्हें अंदर पास करने में क्या दिक्कत आ रही है? हमने देश भर के युवाओं के सुझाव भी जेपीसी को सौंप दिए हैं. वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के विरोध पर नवीन ने साफ कहा, 2019 के चुनाव याद कर लीजिए. जब ओडिशा और लोकसभा के साथ चुनाव हुए थे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी, लेकिन ओडिशा में बीजेडी का मुख्यमंत्री बन गया था. विपक्ष को किसी भी मुद्दे का सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए. अगर तथ्य हैं तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए. संसद में पॉलिसी मेकर बैठे हैं. हमने 545 सांसद चुने हैं, वे इसी काम के लिए हैं और ये कहना कि रायों की ताकत खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल गलत है. 1951 से 1967 तक तो देश में एक साथ चुनाव होते थे, उस वक्त किसी राय की ताकत तो खत्म नहीं हुई थी.

हर चुनाव में जो फंड बचेगा, उसे शिक्षा मंत्रालय को दिया जाए

मार्च में शामिल एक और अन्य छात्र ने एबीपी न्यूज को बताया कि, हर चुनाव में जो फंड बच जाएगा, हमारी मांग है कि उसे शिक्षा मंत्रालय को दिया जाए ताकि शिक्षा का सही विकास हो सके. हम साफ कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को जल्द से जल्द लागू किया जाए. जेपीसी भी बन चुकी है और लेकिन जब तक वन नेशन वन इलेक्शन लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम लगातार इस मुद्दे को आगे बढ़ाते रहेंगे.

सुगमता का जीवन

किसी भी देश के विकास में वहां के व्यापारी वर्ग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसका उल्लेख भारत के दार्शनिक व आर्थिक-राजनीतिक विचारक आचार्य चाणक्य ने अपनी कालजयी पुस्तक 'कौटिल्य का अर्थ शास्त्र' में विशद रूप में किया है और शासक राजा के उसके प्रति कर्तव्यों का भी बखूबी बखान किया है। आचार्य चाणक्य लिखते हैं कि किसी भी राजा को अपने राज्य में व्यापार के फलने-फूलने के लिए ऐसी नीतियों का निर्माण करना चाहिए जिससे वाणिज्य करना सुगम हो सके और व्यापारी वर्ग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपने कारोबार को बढ़ाते हुए राज्य की सुख-समृद्धि में योगदान कर सके क्योंकि तभी कोई राज्य धन-सम्पदा से परिपूर्ण हो सकता है जबकि उसके व्यापारी वर्ग को मजबूर कर साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की छूट मिले। इसके लिए राजा को अपने राजकोष को भरने के लिए अनावश्यक शुल्क प्रणाली से बचना चाहिए और राज-भय का अवांछित प्रयोग नहीं करना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा से उसी प्रकार शुल्क वसूलना चाहिए जिस प्रकार 'मधुमक्खियां' विभिन्न पुष्पों या फूलों से पराग या रस चूस कर अपना 'शहद' का छत्ता बनाती हैं परन्तु राजा को कभी भी स्वयं व्यापारी नहीं बनना चाहिए। यह कार्य उसे व्यापारी वर्ग पर ही छोड़ना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में व्यापार को सर्वांगीण विकास हेतु विशिष्ट महत्ता दी गई है और बताया गया है कि प्रजा में सर्वत्र सुख-शान्ति के लिए व्यापारी वर्ग का कितना महत्व होता है परन्तु भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान व्यापारी वर्ग को लक्षित करने की प्रवृत्ति ने जन्म लिया जिसका प्रमुख कारण यह था कि अंग्रेज अपना शासन चलाने के लिए और भारत की पूंजी को अपने कब्जे में रखने के लिए ऐसी व्यवस्था विकसित करना चाहते थे जिससे देश के व्यापारी वर्ग को खलनायक के रूप में दिखाया जा सके। इसके पीछे उनका उद्देश्य पूरी तरह आर्थिक था। वह अपने देश में बने तैयार माल से भारत के बाजारों को पाट कर यहां के व्यापारी वर्ग की छवि को अपने एजेंट के रूप में विकसित करना चाहते थे, जिसमें वे एक सीमा तक सफल भी रहे क्योंकि उन्होंने इसी व्यापारी वर्ग को सामन्तवाद व रजवाड़ों के चलते ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराने वाले वर्ग के रूप में विकसित कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि उससे पहले जमींदारी प्रथा के चलते भारत में सूद या ब्याज पर धन उपलब्ध कराने का धंधा नहीं होता था परन्तु यह कार्य जमींदार केवल कुछ व्यापारियों के साथ गठजोड़ बनाकर ही करते थे। अतः 21वीं सदी के स्वतन्त्र भारत में यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए अपने व्यापारी वर्ग के साथ बदलते जमाने के अनुरूप व्यवहार करें और राजसत्ता तद्नुरूप अपनी नीतियों में परिवर्तन लाये। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मोदी सरकार के युवा वाणिज्य व उद्योग राज्यमन्त्री श्री जितिन प्रसाद ने बीते कल (शुक्रवार) को लोकसभा में "जन विश्वास विधेयक" की दूसरी खेप लाये जिसमें व्यापार व उद्योग से जुड़े 79 केन्द्रीय कानूनों को परिमार्जित किया गया है। ये 79 केन्द्रीय कानून भारत सरकार के 23 मन्त्रालयों के अधीन आते हैं जिनमें कोयले से लेकर उपभोक्ता मामले, रक्षा, वित्त, स्वास्थ्य, खान, भारी उद्योग व गृह मन्त्रालय तक शामिल हैं। इससे यह आभास लगाया जा सकता है कि भारत के व्यापारियों को कितने मन्त्रालयों की जांच-परख से गुजर कर अपना कारोबार करना होता है। श्री जितिन प्रसाद ने यह संशोधन विधेयक पेश करते हुए बताया कि इन 79 कानूनों के 784 दंड प्रावधानों को इस प्रकार संशोधित किया गया है कि कारोबारियों को छोटी सी गलती के लिए बड़े दंड का भागी न बनना पड़े और अनावश्यक रूप से जेल की हवा न खानी पड़े। इसके साथ ही विधेयक में आम नागरिकों द्वारा सामान्य जीवन शैली के चलते कानून का उल्लंघन करने पर कठोर दंड से बचाने के लिए भी उपाय किये गये हैं और साधारण अपराध के लिए जेल की सजा काटने के बजाय आर्थिक दंड भुगतने के उपाय किये गये हैं। यह विधेयक सदन की प्रवर समिति के परीक्षण के बाद ही कल पेश किया गया परन्तु कांग्रेस के दो सांसदों ने इस पर आपत्ति करते हुए पुनः प्रवर समिति को समीक्षार्थ भेजने की मांग की जिसे अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि अभी तक ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। यह समझने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए कि भारत एक गणराज्य है जिसमें प्रत्येक नागरिक पर विश्वास किया जाना भी जरूरी शर्त होती है। इसी क्रम में मोदी सरकार ने नागरिकों के अपने निजी प्रमाणपत्र स्वयं द्वारा ही सत्यापित किये जाने का कानून बनाया था वरना इससे पहले सत्यापन के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी के दस्तखत जरूरी होते थे। इसकी मूल वजह यही है कि भारत के प्रजातन्त्र में आम लोग ही अपने एक वोट की ताकत से सरकारों का गठन करते हैं। हमारा लोकतन्त्र सहभागिता का लोकतन्त्र कहलाता है अतः हम अंग्रेजों द्वारा स्थापित उन परंपराओं की लकीर पर नहीं चल सकते जो उन्होंने शासक और शासित वर्ग के बीच की दूरी को लगातार चौड़ा बनाये रखने की गरज से खींची थीं। श्री जितिन प्रसाद के अनुसार संगीन व्यापारिक अपराधों की सजाओं में इन संशोधनों के आने के बाद किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी बल्कि केवल उन मामलों में ही ढिलाई की गई है जिनका सम्बन्ध व्यावहारिक तौर पर अनदेखी करने से होता है। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा, श्रमिक संरक्षण व सेना तथा अन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का सवाल है, उनमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। इन 23 कानूनों के 784 प्रावधानों में जो संशोधन किये जा रहे हैं उनमें केवल छोटी-मोटी अनदेखी के लिए ही कड़ी सजा से छूट मिलेगी जिससे व्यापारी व नागरिक आर्थिक दंड व कम सजा भुगत कर स्वयं को सुधार सकें। अतः दंड व्यवस्था जुर्म के स्वरूप के अनुसार ही तय की जा रही है। इस संशोधन विधेयक द्वारा नई दिल्ली नगर निगम के 1994 के कानून को भी परिमार्जित किया जा रहा है और 1988 के मोटर वाहन कानूनों में भी कुछ संशोधन किये गये हैं जिससे आम नागरिकों को भी राहत मिल सके और वे कानूनी पचड़ों से बच सकें। कुल मिलाकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि युवा मन्त्री श्री जितिन प्रसाद नये जमाने की रफ्तार को पहचानते हुए जनता की उस नब्ज पर हाथ रख रहे हैं जिसमें उनकी सुगम जीवन जीने की इच्छा बसती है।

नेपाल की नई सियासत

नेपाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। बालेन्द्र शाह के प्रधानमंत्री बनते ही नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक और पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा नेपाली कांग्रेस के नेता दीपक खड़का को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की गिरफ्तारी के बाद विरोध-प्रदर्शन भी हुए हैं। इन पर आरोप है कि पिछले साल जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 77 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके लिए ये जिम्मेदार हैं। बालेन्द्र शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू किए गए अभियान के तहत की गई है। दीपक खड़का पर आरोप है कि उन्होंने सरकारी व सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किया। जेन-जी विरोध-प्रदर्शन के दौरान उनके घर से भारी मात्रा में नकदी और जले हुए नोट मिले थे। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच दीपक खड़का के बिजनेस साम्राज्य की चर्चा पहले से ही होती रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला एक विशेष आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद शुरू हुआ है। यह आयोग पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में बनाया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओली, रमेश लेखक और तत्कालीन पुलिस प्रमुख चन्द्र कुबेर खापुंग पर केस चलाने की सिफारिश की है। जिन धाराओं के तहत केस बनाया गया है उनमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। इन गिरफ्तारियों के चलते राजनीतिक तनाव पैदा हो गया है। के.पी. शर्मा ओली और उनकी पार्टी ने इसे बदले की राजनीति करार दिया है। जबकि नेपाली कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह गिरफ्तारियां इंसाफ के लिए हैं या यह प्रतिशोध की राजनीति है। ये गिरफ्तारियां नेपाल के युवा लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक परीक्षा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो इस बात का संकेत देती है कि यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों को भी विरोध-प्रदर्शनों के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, जो देश की अशांत राजनीति में एक दुर्लभ घटना है। बालेन्द्र शाह की नई सरकार के लिए, यह «जेनरेशन जेड शहीदों के लिए न्याय» के अपने प्रमुख चुनावी वादे को पूरा करता है जिससे उन युवाओं के बीच उसकी छवि मजबूत होती है जिन्होंने उसे भारी बहुमत से जीत दिलाई। हालांकि इससे ध्रुवीकरण और गहराने का खतरा है। यूएमएल के सड़क प्रदर्शन और संसद में नियोजित विरोध-प्रदर्शन चुनाव के बाद के नाजुक माहौल को अस्थिर कर सकते हैं और टकराव को जन्म दे सकते हैं। नेपाली कांग्रेस का सतर्क रुख संभावित अतिचार के खिलाफ व्यापक विपक्षी एकता में तब्दील हो सकता है। दीर्घकालिक और सफल अभियोजन से कानून का शासन मजबूत हो सकता है और भविष्य में होने वाली दमनकारी कार्रवाइयों को रोका जा सकता है लेकिन विफलता या पक्षपातपूर्ण रवैया जनता के विश्वास को कम कर सकता है और प्रतिशोध की राजनीति से जुड़ी साजिश की थ्योरी को हवा दे सकता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से लंबे समय तक अस्थिरता निवेशकों के विश्वास और चल रहे सुधारों को प्रभावित कर सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जवाबदेही के प्रति नेपाल की प्रतिबद्धता को उजागर करता है लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है।

चारों ओर जमीन से घिरे इस हिमालयी देश में दशकों से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है। 1990 के बाद 32 सरकारें सत्ता में आ चुकी हैं और उनमें से कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। राजशाही के खात्मे के बाद नेपाल में गणतंत्र स्थापित हुआ लेकिन वह भी राजनीतिक स्थिरता लाने में विफल रहा, तब से सरकार में 15 बार बदलाव हो चुके हैं। सत्ता पूर्व माओवादी विद्रोही दल, उदारवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) और नेपाली कांग्रेस के बीच घूमती रही है। खंडित राजनीति के कारण व्यापक जन उदासीनता फैल गई जिससे यह आम धारणा मजबूत हुई कि नेपाल का भ्रष्ट राजनीतिक वर्ग दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से एक आम नागरिकों की दुर्दशा की परवाह नहीं करता है। पिछले वर्ष 8 सितम्बर में भ्रष्टाचार विरोधी जेन-जी आंदोलन ने जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन किए और आंदोलन इतना उग्र हुआ? कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया गया। उसके बाद हुए संसदीय चुनावों में बालेन्द्र शाह के नेतृत्व वाली आरएसपी को अपने बल पर प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ और सरकार बन गई। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के सामने कई चुनौतियां हैं। उनके सामने कर्जों की अदायगी, महंगाई और बेरोजगारी की बड़ी चुनौती है। यद्यपि ओली की गिरफ्तारी चीन के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। विश्लेषक इसे भारत के हित में मान सकते हैं, क्योंकि ओली के शासनकाल में नेपाल और भारत के संबंध बहुत कड़वे रहे। बालेन्द्र शाह को चीन और भारत में भी संतुलन कायम करके चलना होगा जो वहाँ नौकरशाही को व्यवस्थित, कानून के शासन को सुनिश्चित और न्यायपालिका के मजबूत ढांचे को स्थापित करना होगा। नेपाली युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना भी जरूरी है। खाड़ी युद्ध के चलते नेपाल में तेल और ऊर्जा की किल्लत भी बहुत बड़ी विपत्ति है। अगर उन्होंने मामलों को सही ढंग से सम्भाला और राजनीतिक स्थिरता कायम रही तो नेपाल प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। अगर उनसे जरा सी भी चूक हुई तो व्यापक अशांति फैल सकती है। भारत नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार का प्रबल समर्थक है लेकिन बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नेपाल में पूर्व में सरकारें बदलती रहीं लेकिन प्रतिशोध की राजनीति शुरू नहीं हुई इसलिए बालेन्द्र शाह को सतर्कता से काम लेना होगा।

सम्पादकीय...

टैगोर की लाहौर यात्रा

शायद यह बात कुछ अटपटी लगे, मगर तथ्य यही है बलराज साहनी और उनके भाई भीष्म साहनी को एक बार कुछ दिनों के लिए भिक्षा भी मांगनी पड़ी थी, मगर यह भिक्षाटन आर्थिक मजबूरियों के कारण नहीं था। हुआ यूं कि बचपन में दोनों भाइयों को अपने पिता लाला हरबंस लाल साहनी ने शुरूआती शिक्षा एवं संस्कारों के लिए गुरुकुल में भेजा था। वहीं पर उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार भी हुआ। बाल भी पूरी तरह मुंडवाए गए और बकायदा चोटी भी निकाली गई थी। भीष्म साहनी बाद में अंग्रेजी साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए, अम्बाला छावनी के जीएमएन कॉलेज में और बलराज साहनी बम्बई (अब मुम्बई) की फिल्मी दुनिया में प्रवेश से पूर्व शांति निकेतन में हिंदी प्राध्यापक के रूप में नौकरी करने लगे। मगर दो-तीन साल की नौकरी के बाद भीष्म साहनी भी दिल्ली में जा बसे। वहां सारिका व नई कहानियां सरीखी पत्रिकाओं का सम्पादन करने लगे। भीष्म साहनी 1970-80 के दशक में एक बार अम्बाला छावनी आए थे तो उन्होंने बताया था कि वह कुछ समय वहां जीएमएन कॉलेज में पढ़ाते भी रहे थे। यद्यपि भीष्म अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते थे, मगर कहानी लेखन हिंदी में करते थे। अम्बाला छावनी के माल रोड पर लम्बी सैर के मध्य उन्होंने बताया था, 'बचपन में मुझे गुरुकुल में ऋतुपाठ कंठस्थ कराया गया था और भाई बलराज साहनी को 'लघुकौमुदी' कंठस्थ कराया गया था। यज्ञोपवीत के बाद दोनों भाइयों को कुछ दिनों तक परंपरा के अनुसार भिक्षापात्र लेकर भिक्षा मांगने के लिए भी जाना पड़ा था। बाद में हम दोनों को रावलपिंडी के एक आर्य स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। प्रारंभिक संस्कारों की विचित्रता का उल्लेख करते हुए भीष्म साहनी ने बताया था कि एक बार आर्य समाज की अर्द्ध शताब्दी के अवसर पर पिता जी सारे परिवार को महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद के टूटे-फूटे आवास में भी ले गए थे और हम दोनों भाइयों ने स्कूल में श्रवण कुमार के जीवन पर आधारित नाटक का मंच करने में भी लगाया गया था।' भीष्म साहनी से मेरी मुलाकातें बाद में दिल्ली में भी हुई थीं, जब वह एक कहानी पत्रिका 'नई कहानियां' के सम्पादक थे। वैचारिक बदलाव कैसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है, इसका जीवंत विश्लेषण उन दिनों के साक्षात्कारों में भीष्म ने किया था। उन्होंने वे दिन भी दोहराए जब गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर, अपने बलराज साहनी को साथ लेकर शांति निकेतन के लिए धन संग्रह का लक्ष्य लेकर लाहौर भी आए थे और रावलपिंडी भी गए थे। उन्होंने बताया, तब टैगोर को शांति निकेतन के लिए लाहौर के जिन बड़े लोगों ने वित्तीय मदद दी थी, उनमें स. दयाल सिंह मजीठिया (बाद में ट्रिब्यून-समूह के संस्थापक) और सर गंगाराम भी शामिल थे, वहीं पर लाहौर के एक हाल में गुरुदेव को कविता पाठ के लिए भी आमंत्रित किया गया था और उनकी कुछ कविताओं का हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद हरिवंश राय बच्चन व उनकी जीवनसंगिनी तेजी बच्चन ने प्रस्तुत किया था। फैज व एलिस और कासमी भी दर्शकों में मौजूद थे। उसी ब्रेडला हॉल में उदय शंकर व उनकी नृत्यमण्डली ने भी शांति निकेतन के लिए धन संग्रह हेतु अपनी प्रस्तुतियां दी थीं। बाद में यही ब्रेडला हॉल सरदार भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों की गतिविधियों का गुप्त ठिकाना भी बना।

आओ अब जड़ों की ओर लौटें !

जो लोग एक्स (ट्विटर) पर गंभीर विषयों को उठाते रहते हैं उन्हें पता है कि किस तरह बाजारू शक्तियां हमारे दैनिक जीवन पर शिकंजा कसती जा रही हैं। हमारे खाद्यान, सब्ज़ियां, फल व दूध ही नहीं, हमारी दवाईयां और वैक्सीन तक सब पर इन ताकतों का कब्ज़ा है। इनका उद्देश्य न तो हमें स्वस्थ रखना है और न ही सुखी। अरबों- खरबों रुपये का मुनाफा कमाना ही इनका उद्देश्य होता है। इनके लिए हम सब प्रयोगशाला के जानवर हैं, जिन पर ये लगातार खतरनाक परीक्षण करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ताना-बना इस तरह बुना जाता है कि दुनिया के तमाम देशों का नेतृत्व इन ताकतों के चंगुल में फंसा रहे और अपनी प्रजा के हितों का बलिदान करके भी इनके मुनाफे बढ़ाने में मदद करें। इन ताकतों का मुख्य केंद्र है अमरीका। ये सर्वविदित है कि अमरीका की शस्त्र उद्योग लॉबी अमरीकी शासकों को मोहरा बनाकर दुनियाभर में युद्ध करवाती रहती है जिससे उसका माल बिकता रहे। इन ताकतों के आगे अमरीका का सभ्य और सुसंस्कृत समाज भी लाचार है। 'एपस्टीन फाइल्स' में जिस क्रूर, पाशविक प्रवृत्तियों का खुलासा हुआ है। उसके बाद अमरीका के तमाम मशहूर बड़े लोग जेल के सींखचों के पीछे होने चाहिए थे, पर वहां ऐसा नहीं हो रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं कि समरथ को नहीं दोष गुसाईं। जिस तरह के संकट और महामारियां अब लगातार हमारे जनजीवन पर बार-बार हमला करने लगी हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हमारा और हमारी अगली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय है। राष्ट्र का 'सकल घरेलू उत्पादन' या आर्थिक वृद्धि की दर उस राष्ट्र के लोगों के सुखी और स्वस्थ होने का पैमाना नहीं होते। ये आंकड़े उन्हें मुट्ठीभर लोगों को हर्षित करते हैं जो देश के तीन चौथाई संसाधनों पर कब्ज़ा किए बैठे हैं, अगर लोगों की खुशहाली देखना है तो हमें पड़ोसी देश भूटान की ओर रुख करना पड़ेगा, जो अपनी प्रगति को 'सकल घरेलू उत्पादन' के पैमाने पर नहीं बल्कि 'सकल घरेलू उल्लास' (हैप्पीनेस इंडेक्स) के पैमाने पर नापता है। हमें अपने विकास की दिशा और दशा बदलनी चाहिए। देश के 5.5 लाख गांवों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए जिससे आम भारतीय बाजारू शक्तियों के मकड़ जाल से बच कर सुखी और स्वस्थ जीवन जी सके। खाड़ी के देशों में चल रहा भयानक युद्ध, उससे निरंतर बढ़ता ऊर्जा संकट और वायु में घुलता ज़हर पूरी दुनिया के लिए हर दिन चिंता बढ़ा रहा है। इसका बुरा असर अर्थव्यवस्था और रोज़गार पर भी पड़ रहा है। समस्या भयावह होती जा रही है। हर घर में अनिश्चितता और हताशा बढ़ने लगी है। कुकिंग गैस पर से निर्भरता हट कर गोबर के कंडों और लकड़ी पर लौटना पड़ सकता है। क्यों न इस दिशा में एक नई पहल की जाए। सनातन हिन्दू संस्कृति में गाय को मां माना जाता है। धर्म शास्त्र कहते हैं कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। गाय का दूध, उससे बना दही, छाछ, पनीर व घी स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। देशी गाय के गोबर और मूत्र के गुण वैज्ञानिक परीक्षणों से सिद्ध हो चुके हैं। सदियों से हर सनातनी के घर गौ पालन की प्रथा थी। पर शहरीकरण और आधुनिक जीवनशैली ने इस परंपरा को बहुत तेज़ी से नष्ट किया है। गौ वंश और कृषि आधारित जीवन आम भारतीय को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ है। गत 79 वर्षों में हमारी सरकारों ने अगर इस अनुभव का लाभ उठाया होता और आर्थिक विकास के मॉडल को इस तरह दिशा दी होती की गांव का जीवन आत्मनिर्भर बनता तो शहरीकरण और उससे पैदा हुई हज़ारों चुनौतियां आज हमारे सामने मुंह बाय न खड़ी होतीं। गांव की लक्ष्मी गांव में रहती और गांव का युवा गांव में ही रोज़गार पाता तो करोड़ों भारतवासियों को गंदी बस्तियों में नारकीय जीवन न जीना पड़ता। मुझे लगता है कि अगर गौ रक्षा के मामले में एक नई और समेकित सोच को केंद्र में रखते हुए विकास का मॉडल तैयार किया जाए तो गौ वंश और भूमिहीन परिवारों का बहुत कल्याण हो सकता है। ये कोरी कल्पना नहीं है। इस दिशा में हमने एक छोटा सा प्रयोग 20 बरस पहले मथुरा में करके देखा था। जिसके सकारात्मक परिणाम आए। हम इसे आगे इसलिए नहीं चला पाए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता ब्रज के कृष्ण कालीन सरोवरों और वनों को बचाने की थी। ये मॉडल बहुत सरल है। देश के हर गांव में चरागाह की काफ़ी भूमि हुआ करती थी। वोटों की राजनीति ने उसकी बंदरबांट कर दी। फिर भी देश में 10,210,000 हैक्टर भूमि चरागाहों के लिए उपलब्ध है। जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र की 3-4 फ़ीसद है। हर गांव में अनेक भूमिहीन परिवार होते हैं। जिन्हें 'मनरेगा' जैसी योजनाएं चलाकर, साल के कुछ दिन सरकार रोज़गार देती है। हर ज़िले में और उसके गांवों में ऐसे तमाम पढ़े-लिखे सक्षम नौजवान हैं जो सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं। होना यह चाहिए कि गांव के भूमिहीन परिवारों की समिति बना कर उन्हें चरागाहों की भूमि पर चारा उगाने के काम में लगाया जाए। ये चारा फिर हर उस भूमिहीन परिवार को दिया जाए जिसे दानदाता और सरकार नक़द दान की जगह स्वस्थ देशी नस्ल की गाय निःशुल्क उपलब्ध कराए। ये परिवार चरागाह में मेहनत करके आय प्राप्त करें और मुफ्त के चारे से अपने गौ वंश की सेवा करके उसके दुग्ध उत्पादन से अपने परिवार का पालन-पोषण करें और स्वस्थ जीवन जी सकें। आज गांव बच्चों के मुंह में दूध नहीं जाता। गांव को छोड़िये देश के महानगरों तक में नकली दूध, घी, पनीर आदि का कारोबार खूब फलफूल रहा है। हम शहरी लोग ही दूध के नाम पर अपने बच्चों को ज़हर पिला रहे हैं। आज देश में जितना दूध पैदा हो रहा है उससे कई गुना उसकी खपत है। ऐसे में ये बकाया दूध कहां से आ रहा है? दूध के नाम पर क्या पिलाया जा रहा है, इसकी चिंता किसी भी सरकार को नहीं है। छापे पड़ते हैं, नक़ली माल पकड़ा जाता है, खबर छपती है और मामले दबा दिए जाते हैं, इसलिए इस पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। हमने जब ये प्रयोग मथुरा में किया तो हमने दानदाताओं से कहा कि वे एक गांव की चरागाह पर चारा उगाने में आर्थिक मदद करें और किसी को गौ सेवा के नाम पर धन का दान न करें। अपेक्षा के विपरीत हमें ऐसे अनेक उदारमना दानदाता मिल गए और उस गांव के समर्पित नौजवान भी। जिन्होंने इस प्रयोग को सफल बनाने में सहयोग किया। हमारा प्रयोग तो बहुत छोटे स्तर का था। पर आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर और अमरीका में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की मोटे वेतन की नौकरियां छोड़कर कुछ नौजवान मध्य भारत में बहुत बड़े पैमाने पर इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने हज़ारों गरीबों की ज़िंदगी खुशहाल बना दी और इस प्रक्रिया से उत्पन्न गोबर की खाद से बंजर पड़ी ज़मीनों में फलों के बड़े-बड़े बगीचे लगा दिए हैं। शुरू में उनका उपहास करने वाले और उनके रास्ते में रोड़े अटकाने वाले ताक़तवर लोग, नेता और अफ़सर अब उनके सामने हथियार डाल चुके हैं और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है।

हमारे खाद्यान, सब्ज़ियां, फल व दूध ही नहीं, हमारी दवाईयां और वैक्सीन तक सब पर इन ताकतों का कब्ज़ा है। इनका उद्देश्य न तो हमें स्वस्थ रखना है और न ही सुखी। अरबों-खरबों रुपये का मुनाफा कमाना ही इनका उद्देश्य होता है। इनके लिए हम सब प्रयोगशाला के जानवर हैं, जिन पर ये लगातार खतरनाक परीक्षण करते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ताना-बना इस तरह बुना जाता है कि दुनिया के तमाम देशों का नेतृत्व इन ताकतों के चंगुल में फंसा रहे और अपनी प्रजा के हितों का बलिदान करके भी इनके मुनाफे बढ़ाने में मदद करें। इन ताकतों का मुख्य केंद्र है अमरीका। ये सर्वविदित है कि अमरीका की शस्त्र उद्योग लॉबी अमरीकी शासकों को मोहरा बनाकर दुनियाभर में युद्ध करवाती रहती है जिससे उसका माल बिकता रहे। इन ताकतों के आगे अमरीका का सभ्य और सुसंस्कृत समाज भी लाचार है। 'एपस्टीन फाइल्स' में जिस क्रूर, पाशविक प्रवृत्तियों का खुलासा हुआ है। उसके बाद अमरीका के तमाम मशहूर बड़े लोग जेल के सीखचों के पीछे होने चाहिए थे, पर वहां ऐसा नहीं हो रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए हैं कि समरथ को नहीं दोष गुसाईं। जिस तरह के संकट और महामारियां अब लगातार हमारे जनजीवन पर बार-बार हमला करने लगी हैं, उससे यह स्पष्ट है कि हमारा और हमारी अगली पीढ़ियों का भविष्य अंधकारमय है।

विश्व गुरु न सही विश्व मित्र तो मान लो यारो!

भारत अगर एक पाले में खड़ा हो जाता, तो फिर विश्व मित्रता का क्या होता? भारत अगर ईरान से दोस्ती निभाने जाता, तो अमेरिका और इसाइल से मित्रता का क्या होता? सची बात यह है कि इस बात से हमारा विश्व मित्र होने का दावा और भी पुख्ता हो जाता है कि हम अब सही-गलत, न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित, किसी चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम न किसी का समर्थन करते हैं न किसी का विरोध। न किसी की निंदा करते हैं, न किसी की प्रशंसा। हम बस चुप रहते हैं।

भाई ये तो सरासर चीटिंग है। मोदी जी के साथ बल्कि उनके वाले भारत के साथ ही चीटिंग है। बताइए, ये लोग अब मोदी जी को विश्व मित्र मानने से भी इंकार कर रहे हैं। पहले कहते थे कि विश्व गुरु मानने में दिक्कत है। किसी के कहने भर से किसी को विश्व गुरु थोड़े ही मान लिया जाएगा? फिर खुद हमारे कहने से तो होगा भी क्या? खुद ही अपने मुंह से अपने को विश्व गुरु कहते फिरेंगे तो क्या दुनिया मान लेगी? उल्टे अपने मुंह मियां मिट्ठू कहकर मजाक ही उड़ाएगी। वैसे भी विश्व गुरु वह, जिसे दुनिया गुरु माने। घूम-घूमकर दुनिया भर में राजनेताओं के गले पड़ने से और मुलाकातों के सारे वीडियो में आंखियों वाला हिस्सा या तो म्यूट रखने या खी-खी, खी-खी या हे-हे, हे-हे से भरने से, दुनिया किसी को गुरु थोड़े ही मान लेगी। सिर्फ विरोधियों को ठोक-पीट कर गद्दी पर जमे रहने से भी नहीं। टीवी से लेकर हर सड़क, हर चौराहे, हर खंभे पर, एक देश-एक फोटो का विधान चलाने से भी नहीं। कुछ तो हो जिसमें दुनिया आपको सबसे आगे माने और कहे कि हम आपसे सीख रहे हैं, आपके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं! और तो और जब से ट्रंप की अमेरिका की गद्दी पर वापसी हुई है, लंबी फेंकने तक में कोई अब हमें नंबर वन मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टे ट्रंप ने जब से बात-बात पर और बहुत बार तो बेबात भी, जमीन पर नाक रगड़वाना शुरू किया है, उसके बाद से तो विश्व गुरु वाले से सारे ठके फट-फटा ही गए। सच पूछिए तो इसी सब को देखकर मोदी जी ने खुद ही विश्व गुरु की गद्दी की तरफ देखना ही छोड़ दिया और विश्व मित्र पर आ गए। इसमें वैसे भी किसी चीज में सबसे आगे होने टाइप कोई टेंशन ही नहीं है। बस दिल बड़ा होना चाहिए, जिसमें सारी दुनिया समा सके। और दुनिया भर में घूमने का बजट भी होना चाहिए। और बंदे के पास फुर्सत होनी चाहिए, बस। बाकी इकतरफा प्यार की तरह, इकतरफा विश्व मित्र तो कोई भी हो सकता है। पर अब भाई लोगों को विश्व मित्र मानने में भी प्राब्लम है। कह रहे हैं कि काहे के विश्व मित्र, पड़ोसी ईरान से मित्रता तो निभाई नहीं गयी। उससे पहले वेनेजुएला से। उससे जरा सा हट के क्यूबा से। दो साल से फिलिस्तीन से। जरूरत पर किसी के काम आने का गूदा नहीं और दावा विश्व मित्र होने का! लेकिन, यही तो चीटिंग है। कहां तो मोदी जी अपने भारत को विश्व मित्र बनाने में जुटे हुए हैं और कहां विरोधी उससे इस या उस देश का मित्र बनकर दिखाने की बल्कि मित्रता निभाने की मांग कर रहे हैं! क्या ये विरोधियों की छोटी सोच को ही नहीं दिखाता है। ये छोटे-मोटे देशों से दोस्ती करने, दोस्ती निभाने से बड़ी बात, इससे आगे की बात, सोच ही नहीं सकते हैं। पूरा जोर लगाने पर भी इनकी कल्पना तीसरी दुनिया के मित्र होने की बात से आगे जा ही नहीं सकती है। ये क्या जानें विश्व मित्रता का कठिन रास्ता? यह सच है कि अमेरिका-इस्राइल ने ईरान पर हमला किया। बातचीत के बीच में हमला किया। बातचीत के बीच में, साल भर में दूसरी बार हमला किया। लेकिन, यह भी तो सच है कि ईरान ने भी इस्राइल पर और खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों पर जवाबी हमले किए। विश्व दोनों तरफ के हमलों को हम किसी को सही और किसी को गलत कैसे कह सकते हैं? अब क्या सिर्फ इसलिए कि पहले ईरान पर हमला किया गया था, मोदी जी को बस, अमेरिका और इस्राइल को हमलावर बताकर, ईरान के साथ खड़ा हो जाना? या सिर्फ इसलिए ईरान के साथ खड़ा हो जाना कि अमेरिका, हजारों किलोमीटर दूर से आकर यहां क्यों फौजी दखल दे रहा है, एशिया के मामले में अमेरिका का क्या काम है? भारत अगर एक पाले में खड़ा हो जाता, तो फिर विश्व मित्रता का क्या होता? भारत अगर ईरान से दोस्ती निभाने जाता, तो अमेरिका और इस्राइल से मित्रता का क्या होता? सच्ची बात यह है कि इस से हमारा विश्व मित्र होने का दावा और भी पुख्ता हो जाता है कि हम अब सही-गलत, न्याय-अन्याय, उचित-अनुचित, किसी चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम न किसी का समर्थन करते हैं न किसी का विरोध। न किसी की निंदा करते हैं, न किसी की प्रशंसा। हम बस चुप रहते हैं। कोई किसी के राष्ट्राध्यक्ष की हत्या कर दे, हम चुप रहते हैं। कोई बच्चियों के स्कूल पर बम मारकर एक साथ सौ से भी बच्चियों और उनके शिक्षकों की हत्या कर दे, तब भी हम चुप रहते हैं। वैसे चुप तो हम तब भी रहते हैं, जब हमारा कोई मित्र गुजा की दस लाख की आबादी में से, 74 हजार लोगों की हत्या कर दे, जिनमें ज्यादा तादाद महिलाओं और बच्चों की ही है। बेशक, कभी-कभी फोन-वोन कर के बोलते भी हैं, पर सभी को अपनी मित्रता का भरोसा दिलाने के लिए। और सारी दुनिया को यह बताने के लिए कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से हैं। वैसे इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम मित्र भी सिर्फ फिसड्डी टाइप के हैं, दोस्ती निभाना नहीं जानते हैं। चाहे कोई यह इल्जाम तो लगा भी दे कि मोदी जी भारत को ... की तरह दुश्मनियां पालना नहीं आता है और खासतौर पर पड़ोसियों को छोड़कर, समंदर पार वालों से दुश्मनियां पालना नहीं आता है ... अजात-शत्रु कहा जाए, तो भी बेशक बुरा नहीं मानेंगे--पर दोस्ती निभाना नहीं जानने का इल्जाम कोई कैसे लगा सकता है? मोदी जी और ट्रंप जी तथा नेतन्याहू जी की मोहब्बत की तो मिसालें आज सारी दुनिया देती है। ट्रंप जी और नेतन्याहू जी बार-बार उनकी मोहब्बत का इम्तिहान लेते हैं और मोदी जी हर बार साबित करते हैं कि उनकी दोस्ती नहीं टूटेगी। दोस्ती टूटने की छोड़ो, दोनों में जरा ... और हां, कोई शिकायत भी नहीं। इस तक की शिकायत नहीं कि ट्रंप जी दो ... की पोल खोलते रहे, खासकर दोस्त एलन मस्क को क्यों धुमा ले है! दोस्ती निभाएंगे भी जाएंगी, बस जरा दिल मिलने चाहिए। नफरत के लिए मिलें तब भी चलेगा, पर दिल मिलें तो सही! रही पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका-इस्राइल की जंग रुकवाने के लिए दौड़-धूप करने की बात, तो इसका मतलब न तो यह है कि अमेरिका-इस्राइल को मोदी जी की दोस्ती पर भरोसा नहीं है और न इसका मतलब यह है कि मोदी जी का भारत नहीं, पाकिस्तान विश्व मित्र है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात असल में सिर्फ इतनी है कि बातचीत से बात बन भी गयी तो क्या होगा? लेन-देन ही तो होगा। और जयशंकर जी ने तो पहले ही बता दिया है कि लेन-देन करना/कराना तो दलालों का काम है। वॉर रुकवाने का हो तो क्या, दलाली का काम आखिर दलाली का काम है। ऐसा काम पाकिस्तान को ही मुबारक, मोदी जी का भारत दलाली का काम नहीं करेगा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सारा पैन्टनाला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/...)

हनुमान सरोवर पर स्वछता अभियान, रैली व पौधरोपण से दिया स्वछता का संदेश

तमकुही/कुशीनगर।

नमामि गंगे के तहत चल रहे स्वछता पखवाड़ा (16 से 31 मार्च) के अंतर्गत सोमवार को तमकुही रेंज के बरवा राजापाकड़ स्थित हनुमान सरोवर परिसर में स्वछता अभियान, गंगा शपथ, जन-जागरूकता रैली एवं पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वछता का संदेश दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि गंगा और उसके सहायक जल स्रोतों की स्वछता हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने तथा जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने की अपील की।

विशिष्ट अतिथि भाजपा पटहेरवा मंडल अध्यक्ष अमलेश तिवारी ने कहा कि स्वछता अभियान को केवल एक दिन तक सीमित न रखकर इसे जन-आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने युवाओं से आगे आकर समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। जिला परियोजना अधिकारी नमामि गंगे नम्रता भट्ट ने बताया कि स्वछता पखवाड़ा के अंतर्गत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वछता एवं संरक्षण के लिए जनसहभागिता अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान उपस्थित लोगों को गंगा शपथ दिलाई गई, जिसमें सभी ने स्वछता बनाए रखने एवं जल स्रोतों को प्रदूषित न करने का संकल्प लिया। इसके पश्चात निकाली गई जन-जागरूकता रैली ने पूरे क्षेत्र में स्वछता का संदेश प्रसारित किया। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन लाल बिहारी पटेल ने किया। इस अवसर पर मंडल महामंत्री अभिषेक तिवारी, वन दरोगा धीरेंद्र दीक्षित, उदय प्रताप, प्रमोद कुशवाहा, किशोर कुशवाहा, नारायण दास, नंदू वर्मा, काशीनाथ वर्मा, रामनरेश लाल, हरिकेश गुप्ता, भरत पटेल, जितेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

पॉक्सो एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण, चुनौतियों पर हुई चर्चा

पडरौना/कुशीनगर। बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं नियमावली 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों की सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सोमवार को त्रैमासिक अभिसरण बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रभात सिंह की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राय विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार संपन्न हुआ। बैठक में प्रतिभागियों को पॉक्सो अधिनियम की सामान्य समझ, उसकी प्रक्रियाओं एवं प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सहायक व्यक्तियों की भूमिका, उनके कार्यों तथा कार्य के दौरान आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने बेहतर समन्वय के माध्यम से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्रवाई पर बल दिया। कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, सपोर्ट पर्सन, वन स्टॉप सेंटर की सेंटर मैनेजर, चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, जिला बाल संरक्षण इकाई सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव व विदाई समारोह

जौनपुर,। विकासखंड करंज कला के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय प्यारेपुर में वार्षिकोत्सव एवं कक्षा 5 के विद्यार्थियों का विदाई समारोह हर्षोल्लास एवं भावुक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य एवं नाटक की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित अतिथियों व अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रवक्ता अमित कुमार यादव एवं बेसिक शिक्षा विभाग के डीसी रज़ा हसन द्वारा दीप प्रवलित कर किया गया। इस दौरान बच्चों की प्रतिभा की जमकर सराहना की गई। अतिथियों ने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया तथा अन्य बच्चों को भी पुरस्कार वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। विदाई समारोह के दौरान माहौल भावुक हो उठा। कक्षा 5 के छात्र-छात्राओं की विदाई के समय शिक्षक व बच्चे दोनों ही भावुक नजर आए। एक छात्रा द्वारा प्रस्तुत मार्मिक कविता ने सभी की आंखें नम कर दीं। विद्यार्थियों ने अपनी कक्षा अध्यापिका के प्रति प्रेम व सम्मान को भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया, जिससे समारोह यादगार बन गया। इस अवसर पर बच्चों को मेडल, कॉपी, पेन, पेंसिल, पेंसिल बॉक्स एवं पानी की बोतलें वितरित की गईं तथा मिठाइयां खिलाकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। साथ ही विद्यालय में मेगा पीटीएम का आयोजन कर अभिभावकों को बच्चों की शैक्षणिक प्रगति से अवगत कराया गया तथा नए सत्र में अधिक से अधिक नामांकन हेतु प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाध्यापिका नुज़हत अंसारी, शिक्षिकाएं नीता गुप्ता, फरह परवीन, प्रतिमा गुप्ता, निधि मौर्या, प्रियंका श्रीवास्तव सहित अभिभावक मंजू यादव, रेखा यादव, राधा, मीना यादव, साधना यादव (ग्राम प्रधान), विद्या देवी, शैलेश यादव, वेदप्रकाश तिवारी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय परिवार द्वारा सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

के. के. पब्लिक एकेडमी में वार्षिक अंक पत्र वितरण

मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उज्ज्वल भविष्य की कामना

भटनी देवरिया ।

भटनी नगर स्थित के. के. पब्लिक एकेडमी सीनियर सेकेंडरी भटनी में वार्षिक अंक पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रवलित कर किया गया। विद्यालय प्रबंधक बी. के. श्रीवास्तव ने अभिभावकों का स्वागत करते हुए मेधावी छात्रों को आशीर्वाद दिया और उनके सफल जीवन की कामना की।

उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है और बच्चे देश का भविष्य हैं। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों का उज्ज्वल भविष्य बनाना है। उन्होंने बताया कि विद्यालय पिछले कई वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में तहसील, जिला और मंडल स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करता आ रहा है। कार्यकारी निदेशक अजय वर्मा ने विद्यार्थियों की मेहनत और अनुशासन की सराहना करते हुए अभिभावकों से बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने की अपील की तथा सफलता का मूल मंत्र परिश्रम और आत्मविश्वास बताया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। समारोह में प्ले वे से पलक बारी, नर्सरी से आरुषि गुप्ता 97फीसदी, एलकेजी से सलोनी गुप्ता 98फीसदी, यूकेजी से नित्या पाण्डेय 99फीसदी, कक्षा 1 से आयुषी अंबेडकर 99त्न व अंशिका यादव 97फीसदी, कक्षा 2 से कस्तूब श्रीवास्तव 95फीसदी व शिखा यादव 97फीसदी, कक्षा 3 से शिवाय गुप्ता 92फीसदी व परिधि गुप्ता 93फीसदी, कक्षा 4 से इछा कुमारी 99फीसदी व आर्यन मिश्रा 96फीसदी, कक्षा 5 से नरसिंह यादव 95फीसदी व रानी यादव 96फीसदी, कक्षा 6 से उन्नति अस्थाना 99त्न व अर्पित गुप्ता 94फीसदी, कक्षा 7 से ऋषिका 98फीसदी व रेहान अली 97फीसदी, कक्षा 8 से समीर यादव 99त्न, अरना बरनवाल 99त्न व उजवल सिंह 99फीसदी को सम्मानित किया गया।

कुशीनगर दौरे पर आएंगे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव में करेंगे शिरकत

कुशीनगर। उत्तर प्रदेश सरकार के राय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात विभाग दिनेश प्रताप सिंह का जनपद कुशीनगर का एक दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मंत्री 30 मार्च 2026 की सायंकाल अपने निजी आवास जनपद रायबरेली से प्रस्थान कर रात्रि लगभग 10 बजे सर्किट हाउस, कुशीनगर पहुंचेंगे, जहां उनका रात्रि विश्राम निर्धारित है। 31 मार्च 2026 को प्रातः 9:30 बजे मंत्री सर्किट हाउस में जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं संबंधित विभागों के साथ कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इस बैठक में आगामी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियों, व्यवस्थाओं एवं समन्वय की समीक्षा की जाएगी। बैठक के उपरांत मंत्री महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में आयोजित इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव-2026 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन वैश्विक बौद्ध धरोहर, सांस्कृतिक संवाद और पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें देश-विदेश से विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। उद्घाटन समारोह के बाद मंत्री देवरिया के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे श्री हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर श्रद्धालुओं एवं जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे।

अपहरण के बाद मासूम की हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

हाटा/कुशीनगर।

थाना कोतवाली हाटा क्षेत्र के ग्राम गोपाल बिरैचा से अपहृत 12 वर्षीय नाबालिग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक का शव भी बरामद कर लिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार 28 मार्च 2026 को नाबालिग बालक के अपहरण/गायब होने के संबंध में थाना कोतवाली हाटा में मुकदमा संख्या 128/2026 पंजीकृत किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी कसया के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में 29 मार्च 2026 को पुलिस टीम ने घटना का अनावरण करते हुए आरोपी डब्लू गौड़ पुत्र गामा गौड़ निवासी गोपालपुर बिरैचा वार्ड नं. 18 हनुमान

नगर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसका मृतक बालक की मां के साथ अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी बालक को हो गई थी। इसी डर से कि बच्चा यह बात किसी को बता देगा, आरोपी ने उसका अपहरण कर हत्या कर दी और शव छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक राजवीर का शव बरामद किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त गमछे का टुकड़ा एवं एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली हाटा पर धारा 137(2), 103(1) व 238 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत है। आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय दूबे, उप निरीक्षक हरेराम यादव, वरिष्ठ उप निरीक्षक रामचरन सरोज, उप निरीक्षक रुपेन्द्र पाल सिंह, उप निरीक्षक चन्द्रभूषण पांडेय, उप निरीक्षक अतुल तिवारी सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे।

दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने जताई चिंता, केंद्र और राज्य सरकार पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते अपराधों को लेकर सियासत तेज हो गई है. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने दिल्लीवासियों के मन में असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है. देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली में हत्या, लूट, अपहरण, गैंगस्टर गतिविधियों, नशे के कारोबार और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार इजाफा हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले लगभग 12 वर्षों से हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए हैं. चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, पुलिस की कार्यशैली और सुस्त रवैये ने अपराधियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं. उन्होंने कहा कि राजधानी की जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है.

गृहमंत्री से बैठक कर ठोस कदम उठाने की मांग

कांग्रेस नेता ने मांग की कि दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को तुरंत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस रणनीति बनानी चाहिए. उनका कहना है कि हालात को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है.

गुमशुदगी के मामलों ने बढ़ाई चिंता

देवेंद्र यादव ने बताया कि 2026 के जनवरी, फरवरी और मार्च के शुरुआती दिनों में ही लगभग 800 लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें दो तिहाई महिलाएं और लड़कियां हैं. उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर उच्च न्यायालय भी चिंता जता चुका है, लेकिन पुलिस अब तक प्रभावी समाधान निकालने में असफल रही है. यहां तक कि पुलिस आयुक्त को कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने जैसे कदम उठाने पड़े हैं.

उन्होंने कहा कि 2026-27 के दिल्ली बजट में सामाजिक कल्याण के लिए 10,537 करोड़ रुपये और महिलाओं एवं बाल विकास के लिए 7,406 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसके बावजूद जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार दावे तो करती है, लेकिन अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है.

हत्या की घटनाओं ने खोली कानून व्यवस्था की पोल

देवेंद्र यादव ने हाल के कुछ मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तम नगर में होली के दिन 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या, भजनपुरा में ईद के दिन चाकू मारकर हत्या, रोहिणी में गोली मारकर हत्या और बवाना एवं नंद नगरी में हुई हत्याएं यह साबित करती हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. उन्होंने कहा कि अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है.

नक्सलवाद खत्म, आदिवासियों को मिला असली न्याय - शाह

नई दिल्ली। लोकसभा में नक्सलवाद पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि देश में नक्सलवाद अब लगभग समाप्त हो चुका है और आदिवासी इलाकों में असली न्याय पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि 2014 के बाद केंद्र सरकार की सख्त नीति, सुरक्षा अभियान और विकास योजनाओं के कारण संभव हुआ है। शाह ने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने नक्सलियों से बातचीत नहीं, बल्कि उन्हें खत्म कर विकास को आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि जो हथियार उठाएगा, उसे कीमत चुकानी पड़ेगी।

उन्होंने दावा किया कि नक्सलियों का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, पोलित ब्यूरो और कमेटी अब खत्म हो चुकी है। कई मारे गए, कई ने सरेंडर किया और कुछ फरार हैं। शाह ने कहा कि देश अब नक्सलमुक्त होने की स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि कई बड़े ऑपरेशन जैसे कुड़, थंडरस्टॉर्म और ब्लैक फॉरेस्ट चलाए गए, जिनमें भारी मात्रा में हथियार, आईईडी फैक्ट्री और अनाज बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा के बड़े इलाके अब नक्सल प्रभाव से बाहर आ चुके हैं। सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस की भूमिका को उन्होंने अहम बताया।

भोले आदिवासियों को बहकाकर हथियार थमाए गए

आजादी के समय देश संसाधनों की कमी और विकास की चुनौतियों से जूझ रहा था।

कई दूर-दराज के इलाकों तक सरकार की पहुंच नहीं थी, सड़कों और सुविधाओं का अभाव था। ऐसे हालात में कुछ संगठनों ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया। जहां राज्य की पकड़ कम थी, उन्हीं इलाकों को रेड कॉरिडोर बनाया गया। भोले-भाले आदिवासियों को भेदभाव और शोषण के नाम पर भड़काया गया और उनके हाथों में हथियार थमा दिए गए। हकीकत यह है कि इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध भेदभाव नहीं, बल्कि विकास की कमी थी, जिसका इस्तेमाल कर हिंसा को बढ़ावा दिया गया।

शाह ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए?

गृह मंत्री ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। उन्होंने एनएसी, कुछ नेताओं और कथित नक्सल समर्थकों के संबंधों का जिक्र किया। शाह ने कहा कि यह मुद्दा यहीं नहीं रुकेगा और चुनाव तक जाएगा। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए और कहा कि देश को जवाब देना होगा कि नक्सलवाद के दौर में क्या हुआ।

सरकार ने क्या रणनीति अपनाई?

शाह ने बताया कि सरकार ने ऑल एजेंसी अप्रोच अपनाई, जिसमें सीएपीएफ, राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया गया। फंडिंग और सपोर्ट सिस्टम पर प्रहार किया गया। सरेंडर नीति लागू की गई, जिसमें आत्मसमर्पण करने वालों को आर्थिक मदद और पुनर्वास दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर गांव तक अपनी पहुंच बनाई, जिससे नक्सलवाद कमजोर हुआ। उन्होंने आगे कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास हुआ। हजारों किलोमीटर सड़कें बनीं, मोबाइल टावर लगाए गए, बैंक, एटीएम और डाकघर खोले गए। शिक्षा के लिए एकलव्य स्कूल, आईटीआई और कौशल केंद्र बनाए गए। उन्होंने कहा कि विकास ही नक्सलवाद खत्म करने का सबसे बड़ा कारण बना।

नक्सलवाद की जड़ क्या थी?

शाह ने कहा कि नक्सलवाद गरीबी से नहीं, बल्कि विचारधारा से पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि यह विचारधारा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और बंदूक के जरिए सत्ता चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासियों को बरगलाकर उनके हाथ में हथियार दिए गए और विकास को रोका गया। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार आगे भी सख्ती और विकास दोनों पर काम जारी रखेगी। उन्होंने आदिवासी समाज को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा और विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अब देश बंदूक से नहीं, संविधान से चलेगा और यही असली जीत है।

राहुल गांधी पर भी बोला हमला

संसद में शाह ने कहा कि राहुल गांधी अपने लंबे करियर में नक्सलों और नक्सल समर्थकों के साथ देखे गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंट जुड़े थे, इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। 2018 में हैदराबाद में घुमांडी विट्ठल राव, राहुल ने उस गद्दार से मुलाकात की। 2025 कॉर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस के साथ मुलाकात की। हिड़मा जब मारा गया, तब इंडिया गेट पर कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा के नारे लगे। इन नारों के वीडियो को राहुल गांधी ने खुद पोस्ट किया है। नक्सलों का समर्थन करते-करते एक पार्टी और उसके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं।

सुप्रिया श्रीनेत बोलीं- हिमंता सरकार भ्रष्टाचार में दबी

गुवाहाटी। असम के गुवाहाटी पहुंची कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा- हमें पूरा भरोसा है कि असम में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहां पिछले 10 सालों से एक ही सरकार, बीजेपी की सरकार है। हिमंता सरकार भ्रष्टाचार में दबी हुई है। इस सरकार के कार्यकाल में अनगिनत घोटाले हुए हैं। पिछले 10 सालों में हिमंत बिस्वा सरमा और उनके परिवार की संपत्ति में 665फीसदी की चौंका देने वाली दर से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि असम की जनता को ऐसी कोई समृद्धि देखने को नहीं मिली है। असम के लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा है। असम के 21 लाख शिक्षित युवाओं ने बेरोजगारी एक्सचेंज में अपना पंजीकरण कराया है। उनमें से केवल 0.1फीसदी को ही नौकरियां मिल पा रही हैं। श्रीनेत ने कहा कि असम पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। जनता अब निर्णायक फैसला लेगी और उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। क्योंकि अहंकार, फूट डालने की प्रवृत्ति और खुला भ्रष्टाचार ही असल में पिछले 10 सालों और विशेष रूप से पिछले 5 सालों की पहचान है।

पश्चिम एशिया संकट पर राजनीति नहीं, समाधान चाहिए; प्रियंका गांधी बोलीं- एकजुट रहना जरूरी

नई दिल्ली।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि युद्ध के मुद्दे पर राजनीति करना सही नहीं है। उन्होंने पूछा कि खाड़ी में फंसे भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार का क्या प्लान है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में कहा लोगों की जान खतरे में है क्योंकि ऊपर से बम बरस रहे हैं। प्रधानमंत्री इस पर क्या कर रहे हैं? लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का क्या प्लान है?

युद्ध और संकट के मुद्दे पर राजनीति करना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरा देश इस मसले पर एकजुट है, लेकिन समस्या का समाधान ढूंढना जरूरी है। इसके लिए संसद में चर्चा होनी चाहिए ताकि सुझाव दिए जा सकें और समाधान निकाला जा सके। प्रियंका गांधी ने मौजूदा संकट का हवाला देते हुए कहा जैसे-जैसे यह युद्ध जारी है, समस्याएं बढ़ रही हैं। आज गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि कोई खरीद नहीं पा रहा। भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कमी होगी। ऐसे में सरकार का समाधान क्या है? इससे पहले रविवार को केरल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि खाड़ी में युद्ध के दौरान भारत में इसके प्रभाव को न्यूनतम रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने से ही वे सभी देशों के नेताओं के संपर्क में हैं और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता है। प्रियंका गांधी के आरोपों के जवाब में मोदी ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस के बयान खाड़ी में रहने वाले भारतीयों के लिए खतरनाक हैं। पीएम ने कहा लगभग एक करोड़ भारतीयों की जान जोखिम में डालकर कांग्रेस राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है।

असम में पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले पीएम मोदी- राज्य में विकास के लिए शांति पहली शर्त

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद नामक जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत नमो ऐप के माध्यम से असम के पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस बातचीत में पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के विचार जाने और उन्हें चुनाव में जीत के लिए कड़ी मेहनत का गुरुमंत्र दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीते एक दशक में असम में तेज विकास होने की बात भी कही।

सिर्फ कागजों पर समझौते करती थी कांग्रेस

असम में भाजपा के बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सबसे पहली शर्त शांति है। उन्होंने कहा कि राज्य लंबे समय तक अस्थिरता से जूझा है, लेकिन पिछले दशक में चीजें बदल गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पूर्वोत्तर में विभिन्न संगठनों के साथ 12 शांति समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं को लोगों को यह याद दिलाना चाहिए कि कांग्रेस सरकार सिर्फ सुर्खियां बटोरने और लोगों को गुमराह करने के लिए कागजों पर ही समझौते करती थी।

असम ने अस्थिरता का लंबा दौर देखा है

प्रधानमंत्री ने कहा, हमने वह दौर देखा है जब असम हिंसा की आग में जल रहा था। असम में लंबे समय तक अस्थिरता रही, लेकिन पिछले दशक में स्थितियां बदली हैं। आज भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रयासों से राज्य में नया आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान शांति समझौतों को नजरअंदाज किया गया और युवाओं को भटकने के लिए छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, कांग्रेस शासन में उग्रवादी और छात्र संगठनों के साथ कोई भी समझौता सफल नहीं हुआ। कांग्रेस ने बोडो समुदाय के साथ विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने शांति स्थापित करने और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए काम किया है तथा शांति समझौतों को जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू किया जा रहा है।

लोगों को कांग्रेस का कार्यकाल याद दिलाने की जरूरत

प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्होंने पहली बार वोट करने जा रहे मतदाताओं को पूर्व की कांग्रेस सरकारों के कार्यकाल को याद दिलाने की जरूरत है और एक छोटी सी गलती राज्य को पीछे धकेल सकती है। पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा-एनडीए की सरकार की जीत की हैट्रिक के लिए कड़ी मेहनत करने की अपील की।

पार्टी कार्यकर्ताओं से जीत के लिए मेहनत करने की अपील की

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी लोग असम में भाजपा-एनडीए सरकार की हैट्रिक सुनिश्चित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, मैं असम भाजपा के कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। मैं भी आप की तरह एक कार्यकर्ता हूं। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, मैं उसे निभाता हूं। आज बूथ स्तर पर आपसे संवाद का अवसर मिला है। मुझे पता है कि आप सभी मेरा बूथ, सबसे मजबूत के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से राज्य में प्रसारित हो रहे एआई-जनित वीडियो से लोगों को सतर्क करने को भी कहा। 126 सदस्यीय असम विधानसभा के लिए चुनाव 9 अप्रैल को होंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2016 से राज्य में सत्ता में है।

चुनाव प्रचार में राहुल ने मेड इन इंडिया पर पूछे सवाल; भाजपा को छिपी हुई ताकत बताया

कोट्टायम / तिरुवनंतपुरम।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केरल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी केरल दौरे पर सबरीमाला मुद्दे पर चुप रहे। यह भाजपा और एलडीएफ के मिलकर काम करने का संकेत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस, केरल विधानसभा चुनाव 2026 में माकपा और भाजपा से मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ट्रंप के दबाव में हैं। यह सभी जानते हैं। प्रधानमंत्री केरल के मुख्यमंत्री को भी नियंत्रित करते हैं।

साइकिल पर कांग्रेस का चुनाव प्रचार?

कोट्टायम में राहुल ने पार्टी नेताओं के साथ साइकिल पर चुनाव प्रचार भी किया। राहुल गांधी पुथुप्पल्ली के पम्पाडी बस स्टैंड पर आयोजित कांग्रेस पार्टी की जनसभा में भाग लेने के बाद साइकिल से रवाना हुए।

सबरीमाला और भाजपा-एलडीएफ गठजोड़

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एलडीएफ नेताओं ने अयप्पा मंदिर से सोना चुराया। उन्होंने पीतल से उसे बदल दिया। प्रधानमंत्री भाजपा को नुकसान से बचाने के लिए चुप रहे। यह दर्शाता है कि भाजपा और एलडीएफ साथ काम कर रहे हैं। यह भी दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को धर्म या मंदिरों की परवाह नहीं है। यूडीएफ सरकार मंदिर से संबंधित कथित अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करेगी।

अंबानी-अदाणी का जिक्र कर

पूछा- रोजगार की उम्मीद कैसे करें?

मेड इन इंडिया का मुद्दा उठाते हुए राहुल ने कहा, जब मैंने भाषण शुरू किया, तो मेरी नजर माइक पर पड़ी। उस पर मेड इन चाइना लिखा था। इस माइक पर मूल देश भारत या मूल राज्य केरल क्यों नहीं लिखा है? अगर हमारे पास भारत में बनी चीजें ही नहीं होंगी, तो हम केरल के युवाओं के लिए रोजगार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा, अगर केरल का भविष्य केवल एक या दो कंपनियों के हाथों में ही रहेगा, तो हम केरल में चीजों का उत्पादन कैसे कर पाएंगे? उन्होंने मुख्यमंत्री विजयन और प्रधानमंत्री पर कॉर्पोरेट के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा, दोनों मिलकर इस देश को अदाणी और अंबानी के हाथों में सौंप रहे हैं।

एलडीएफ नेतृत्व भ्रष्ट

राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा यूडीएफ को नहीं चाहती। उन्हें पता है कि देश में कांग्रेस ही उन्हें चुनौती दे सकती है। भाजपा समझती है कि एलडीएफ उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती नहीं दे सकता। दिल्ली में सत्ता में होने पर केरल में कोई भी एलडीएफ सरकार उनके नियंत्रण में रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से लड़ने वालों पर हमला होता है। राहुल ने बताया कि उन पर 36 मामले हैं और 55 घंटे लगातार पूछताछ हुई। केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती। एलडीएफ नेतृत्व भ्रष्ट है, लेकिन भाजपा का उन पर कोई दबाव नहीं है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, मंदिरों और धर्म की बात करते हैं। लेकिन पलक्कड़ दौरे पर वे सबरीमाला की घटना को भूल गए।

एलडीएफ पर कॉर्पोरेट-समर्थन के आरोप

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एलडीएफ अब वामपंथी पार्टी जैसा व्यवहार नहीं करता। उनकी नीतियां भाजपा की तरह ही कॉर्पोरेट-समर्थित हैं।

यूडीएफ ने अतीत में रबर किसानों का समर्थन किया था। एलडीएफ रबर श्रमिकों को मुआवजा देने से इन्कार करता है। कांग्रेस रबर किसानों और श्रमिकों को मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाएगी। बाजार के प्रतिकूल होने पर उन्हें व्यवस्थित रूप से संरक्षित और मुआवजा दिया जाएगा।

स्पेन ने अमेरिका के लिए एयरस्पेस बंद किया

मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक; कहा-ईरान युद्ध अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ

तेल अवीव/तेहरान।

स्पेन ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है। साथ ही, मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। स्पेन की रक्षा मंत्री मार्गारीटा रोब्लेस ने कहा कि देश अपने एयरस्पेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए नहीं करने देगा। इस फैसले के बाद अमेरिकी विमानों को रूट बदलने पड़ेंगे, हालांकि मानवीय और आपातकालीन उड़ानों को छूट दी गई है। स्पेन के अर्थव्यवस्था मंत्री कार्लोस कुएर्पो ने कहा कि यह फैसला एकतरफा और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ शुरू युद्ध का समर्थन न करने के आधार पर लिया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पहले ही अमेरिका-इजराइल सैन्य अभियान की आलोचना कर चुके हैं। वहीं, डोनाल्ड ट्रम्प ने इस फैसले के जवाब में व्यापारिक कार्रवाई की धमकी दी है। इस निर्णय के बाद अमेरिका और स्पेन के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की संभावना है।

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 31वां दिन है। पूरे एक महीने बाद भी इस युद्ध की आग बुझती नजर नहीं आ रही है। ईरान ने इजरायल की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई और रिफाइनरी के ऊपर से काला धुआं निकलता नजर आया। ईरान ने दावा किया है कि उसने हाइफा रिफाइनरी को निशाना बनाया है। वहीं हिजबुल्ला भी दावा कर रहा है कि उसने हाइफा में एक नौसेनिक अड्डे को निशाना बनाया है। हिजबुल्ला ने नौसेनिक अड्डे पर मिसाइलों की बौछार की है। हिजबुल्ला का यह दावा हाइफा की

ईरान-हिजबुल्ला का इजरायल पर डबल अटैक, ऑयल रिफाइनरी और सैन्य अड्डों पर मिसाइलों की बौछार

तेल रिफाइनरी में मिसाइल हमले के बाद लगी आग के बाद किया गया। यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि आग सीधे मिसाइल लगने से लगी थी या फिर मिसाइल के टुकड़ों के गिरने से। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर इस युद्ध में ये दूसरी बार हमला हुआ है। इस मिसाइल अटैक के बाद इजरायल के अग्निशमन और बचाव सेवाओं ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इजरायल के पास केवल दो ऑयल रिफाइनरी हैं। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र को निशाना बनाया है। इस युद्ध में ईरान के भीतर कई पेट्रोकेमिकल संयंत्रों पर भी हमले हुए हैं। इजरायली सेना ने आज सोमवार को जानकारी दी कि उन्होंने वेस्ट बैंक में CNN की टीम पर हमला करने और उन्हें हिरासत में लेने वाली बटालियन को सस्पेंड कर दिया है। एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने बताया कि इस रिजर्व बटालियन में सैकड़ों ऐसे रिजर्विस्ट शामिल हैं जिन्होंने अति-रूढ़िवादी नेतजाह येहुदा बटालियन में सेवाएं दी हैं। इसे तुरंत वेस्ट बैंक से हटा लिया जाएगा और अगली सूचना तक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा।

सीएम ममता बनर्जी का तीखा प्रहार, कहा- चुनाव खत्म होते ही गैस-कैश देना बंद कर देगी भाजपा

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेलदा में एक बड़ी चुनावी रैली की। इस रैली में उन्होंने भाजपा की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने जनता को चेतावनी देते हुए कहा, भाजपा चुनाव खत्म होते ही गैस और कैश देना बंद कर देगी। उन्होंने इसे भाजपा की एक सोची-समझी चाल और चुनावी खेल करार दिया। ममता बनर्जी ने भाजपा पर समाज को बांटने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज के विभिन्न वर्गों के बीच नफरत और झगड़े पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, भाजपा इस तनावपूर्ण स्थिति का फायदा उठाकर देश को लूटना चाहती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भाजपा के बहकावे में न आएं। ममता बनर्जी ने साफ किया कि भाजपा केवल सत्ता के लिए लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है और चुनाव के बाद वह अपने वादों से मुकर जाएगी। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह की राजनीतिक चार्जशीट का जवाब देते हुए कहा, पहली चार्जशीट तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ होनी चाहिए, जो दंगे भड़काकर सत्ता में आए। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम से लेकर प्रशासन और पुलिस तक को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने भाजपा के कहने पर कई काबिल अधिकारियों को हटा दिया है, जो अधिकारियों का अपमान है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा किसी धर्म से प्यार नहीं करती, वह सिर्फ ढोंग करती है। उन्होंने कहा, जिस तरह से वे देश चला रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एक या दो महीने के भीतर दिल्ली से भागना पड़ेगा। रैली में ममता बनर्जी ने 2016 की नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय लाइनों में लगकर करीब 200 लोगों की जान गई थी। उन्होंने वोटर लिस्ट से मुस्लिमों, हिंदुओं और आदिवासियों के नाम हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने वादा किया कि जिनकी पहचान वोटर लिस्ट से मिटाई गई है, उनकी पार्टी उन्हें मुफ्त कानूनी मदद देगी।

पिछले 15 वर्षों में अपनी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 100-दिन की रोजगार गारंटी, पक्के मकानों के निर्माण और सड़कों जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए फंड रोक दिया है। बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने इन प्रोजेक्ट्स को अपने फंड से चला रही है। उन्होंने बंगाल युवा साथी योजना का बचाव करते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं को मिलने वाले 1500 रुपये उनकी पॉकेट मनी है। उन्होंने दावा किया कि देश में बेरोजगारी 40 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि बंगाल में इसे कम किया गया है।